नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 236
दि. 30.05.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मौत बांटती शराब: मेथेनॉल के लालच ने निगल ली 18 जिंदगियां, पुणे से पिंपरी-चिंचवड़ तक मातम

महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई मौतों ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। कुछ रुपये अधिक कमाने की हवस ने कई परिवारों के चिराग बुझा दिए और देखते ही देखते फुगेवाडी तथा हडपसर के अनेक घरों में मातम पसर गया। संदिग्ध जहरीली शराब पीने से अब तक कम से कम 18 लोगों की मौत होने का दावा किया जा रहा है, जबकि कई अन्य लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इस दर्दनाक घटना के सामने आने के बाद राज्य सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, वहीं पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुख्य तस्कर सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

यह घटना केवल जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला नहीं है, बल्कि अवैध शराब कारोबार, प्रशासनिक निगरानी की कमी और मुनाफाखोरी की उस भयावह मानसिकता को उजागर करती है, जिसने निर्दोष लोगों की जान ले ली। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शराब की मात्रा बढ़ाने और अधिक लाभ कमाने के लिए उसमें सामान्य सीमा से कहीं अधिक मेथेनॉल मिला दिया गया था। यही जहरीला रसायन मौत का कारण बना।

पुलिस और आबकारी विभाग के अनुसार सबसे पहले पिंपरी-चिंचवड़ के फुगेवाडी इलाके में अचानक कई लोगों की तबीयत बिगड़ने की खबरें सामने आईं। कुछ ही घंटों में कई लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पुणे के हडपसर स्थित पांढरे मला क्षेत्र से भी इसी तरह के मामले सामने आने लगे। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती गई और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों का कहना है

कि मृतकों में अधिकांश मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग शामिल हैं, जो सस्ती शराब खरीदकर उसका सेवन करते थे। पुलिस के अनुसार फुगेवाडी में सात और हडपसर क्षेत्र में कम से कम पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं विपक्षी नेताओं और स्थानीय लोगों का दावा है कि कुल मृतकों की संख्या 18 तक पहुंच चुकी है। कई लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। चिकित्सकों का कहना है कि मेथेनॉल युक्त शराब का सेवन करने पर आंखों की रोशनी जाने, किडनी और लीवर फेल होने तथा अंततः मृत्यु होने का खतरा रहता है।

जांच के दौरान जो कहानी सामने आई है, उसने अवैध शराब कारोबार की पूरी काली दुनिया को उजागर कर दिया है। पुलिस के अनुसार पुणे जिले के हवेली तहसील के उरळी कांचन गांव का निवासी राधेश्याम प्रजापती कथित रूप से अवैध शराब तैयार करने का काम करता था। तैयार शराब बाद में योगेश वानखेड़े नामक आरोपी तक पहुंचाई जाती थी। जांच एजेंसियों का कहना है कि योगेश वानखेड़े इस अवैध कारोबार का महत्वपूर्ण हिस्सा था और वह शराब को पुणे तथा पिंपरी-चिंचवड़ के विभिन्न अवैध अड्डों तक पहुंचाने का काम करता था।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार योगेश वानखेड़े कोई नया अपराधी नहीं है। उसके खिलाफ पहले भी शराब तस्करी और अवैध बिक्री के तीन मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद वह इस कारोबार में सक्रिय रहा। जांचकर्ताओं का आरोप है कि इस बार अधिक मुनाफा कमाने के लिए उसने खरीदी गई शराब में मेथेनॉल मिला दिया। सामान्यतः अवैध शराब बनाने वाले लोग मात्रा बढ़ाने के लिए कुछ रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस मामले में कथित तौर पर मेथेनॉल की मात्रा जरूरत से कहीं अधिक थी। परिणामस्वरूप शराब पूरी तरह जहरीली बन गई और उसे पीने वाले लोगों की जान पर बन आई।

राज्य आबकारी आयुक्त अतुल कानडे ने बताया कि फुगेवाडी में हुई मौतों के बाद विभाग ने तत्काल जांच शुरू कर दी थी। इसी दौरान योगेश वानखेड़े को हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उसके दोनों इलाकों में शराब आपूर्ति से जुड़े होने की जानकारी सामने आई। बाद में उसे आगे की कार्रवाई के लिए पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस को सौंप दिया गया।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा है कि पुलिस इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केवल शराब बेचने वालों को पकड़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस अवैध कारोबार के पीछे मौजूद पूरे तंत्र की पहचान कर उसे खत्म करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मामले में आगे भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी ओर इस घटना को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के नेता रोहित पवार ने हडपसर इलाके में एक कथित अवैध शराब अड्डे पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया और वहां तोड़फोड़ भी की। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में अवैध कारोबार खुलेआम चल रहा है और प्रशासन उसे रोकने में विफल साबित हुआ है। रोहित पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 18 तक पहुंच चुकी है और इसके लिए सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण नहीं है। यदि समय रहते कार्रवाई की जाती तो इतनी बड़ी त्रासदी टाली जा सकती थी। वहीं सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा।

इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर अवैध शराब का कारोबार इतनी आसानी से कैसे फल-फूल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल छापेमारी और गिरफ्तारी से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। इसके लिए उत्पादन से लेकर वितरण तक पूरे नेटवर्क पर लगातार निगरानी, कड़े कानूनों का प्रभावी पालन और स्थानीय स्तर पर जनजागरूकता आवश्यक है।

जनगणना से बदलेगी विकास की तस्वीर, बंगाल में एक अगस्त से शुरू होगा व्यापक आंकड़ा अभियान

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से प्रतीक्षित जनगणना प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने तय किया है कि एक अगस्त से पूरे प्रदेश में जनगणना का कार्य शुरू किया जाएगा, जो अगले वर्ष फरवरी के अंत तक चलेगा। इस घोषणा के साथ ही राज्य में जनसंख्या, विकास योजनाओं और जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। प्रशासन का दावा है कि यह अभियान पूरी तरह विकास और बेहतर प्रशासनिक योजना निर्माण के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है, जबकि राजनीतिक गलियारों में इसके विभिन्न मायने निकाले जा रहे हैं।

राज्य सचिवालय नबन्ना में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद इस संबंध में जानकारी देते हुए विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को अब जनगणना के मामले में देश के अन्य राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि सटीक और अद्यतन जनसंख्या आंकड़े किसी भी सरकार के लिए विकास योजनाएं तैयार करने, संसाधनों का वितरण करने और भविष्य की नीतियां निर्धारित करने का आधार होते हैं।

यदि आंकड़े सही नहीं होंगे तो योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाने में कठिनाई होगी।

उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जनगणना केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी से सफल होने वाला राष्ट्रीय दायित्व है। उन्होंने कहा कि हर परिवार को सही जानकारी देकर इस प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए ताकि राज्य के विकास का वास्तविक खाका तैयार किया जा सके। प्रशासनिक अधिकारियों का भी मानना है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास, पेयजल, परिवहन और शहरी विकास जैसी योजनाओं की सफलता काफी हद तक जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करती है।

हालांकि जनगणना की घोषणा के साथ ही पश्चिम बंगाल की बदलती जनसांख्यिकीय स्थिति का मुद्दा भी चर्चा के केंद्र में आ गया है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के कुछ सीमावर्ती जिलों में आबादी के तेजी से बदलते स्वरूप को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने दावा किया कि सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ के कारण कई क्षेत्रों की जनसंख्या संरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। उनके अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में पिछले वर्षों के दौरान जनसंख्या वृद्धि का पैटर्न सामान्य से अलग रहा है, जिसकी विस्तृत जानकारी जनगणना के बाद सामने आ सकती है।

उन्होंने बांग्लादेश से लगने वाली पश्चिम बंगाल की लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का उल्लेख करते हुए कहा कि कई क्षेत्रों में अब भी सीमा सुरक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव है। उनका आरोप है कि लगभग 600 किलोमीटर लंबी सीमा के कई हिस्सों में पूर्ण रूप से बाड़बंदी नहीं हो सकी है, जिससे अवैध घुसपैठ की समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति का असर केवल सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय संतुलन पर भी पड़ा है।

शुभेंदु अधिकारी ने पूर्ववर्ती राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सीमा क्षेत्रों में आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण सीमा सुरक्षा बल को कई स्थानों पर बाड़ लगाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके अनुसार यदि समय रहते आवश्यक कदम उठाए गए होते तो वर्तमान स्थिति काफी हद तक नियंत्रित की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़े राज्य की वास्तविक स्थिति को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में जनसंख्या और जनसांख्यिकीय परिवर्तन का विषय लंबे समय से राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने दृष्टिकोण से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। ऐसे में आगामी जनगणना के आंकड़े राज्य की राजनीति और नीतिगत निर्णयों पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जनगणना को किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए और इसका उद्देश्य केवल वास्तविक आंकड़े जुटाकर विकास की दिशा तय करना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जनगणना किसी भी राज्य के लिए केवल जनसंख्या गिनने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक बदलावों का व्यापक दस्तावेज भी होती है। इससे यह पता चलता है कि किस क्षेत्र में कितनी आबादी बढ़ी है, किन इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता अधिक है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच कैसी है तथा भविष्य में किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। इसी आधार पर सरकारें बजट आवंटन, नई परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करती हैं।

पश्चिम बंगाल में शुरू होने जा रही यह जनगणना इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन देखने को मिला है।

800 रुपये की कथित रिश्वत का मामला, 19 साल बाद पूर्व सरकारी कर्मचारी को मिली राहत

ठाणे। लगभग दो दशक तक चले कानूनी संघर्ष के बाद ठाणे की विशेष सीबीआई अदालत ने केंद्र सरकार के एक पूर्व कर्मचारी को कथित रिश्वतखोरी के मामले में बरी कर दिया है। वर्ष 2006 में 800 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए अरविंद मोतीराम सावंत को अदालत ने सभी आरोपों से मुक्त करते हुए कहा कि केवल रकम की बरामदगी किसी व्यक्ति को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि रिश्वत मांगने और उसे स्वीकार करने के आरोप को साबित करने के लिए ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य आवश्यक होते हैं, जो इस मामले में अभियोजन पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका।

विशेष न्यायाधीश डी.एस. देशमुख ने अपने फैसले में कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत किसी भी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि उसने रिश्वत की मांग की थी और उसे जानबूझकर स्वीकार किया था। यदि मांग का तथ्य ही संदेह से परे सिद्ध नहीं होता, तो केवल आरोपी के पास से बरामद धनराशि को दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने सावंत को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

यह मामला अगस्त 2006 का है, जब अरविंद मोतीराम सावंत नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर स्थित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) कार्यालय में क्लर्क के रूप में कार्यरत थे। उस समय एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसे एक निजी कंपनी से संबंधित निगमन दस्तावेज और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की प्रमाणित प्रतियां तत्काल चाहिए थीं ताकि वह एक कथित अवैध निर्माण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सके। शिकायतकर्ता का दावा था कि दस्तावेज जल्दी उपलब्ध कराने के बदले सावंत ने पहले 1,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसे बाद में घटाकर 800 रुपये कर दिया गया।

शिकायत मिलने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले की जांच शुरू की और 22 अगस्त 2006 को एक ट्रैप ऑपरेशन आयोजित किया। सीबीआई के अनुसार, कार्रवाई के दौरान आरोपी के पास से रासायनिक पदार्थ लगे नोट बरामद किए गए थे। इसी आधार पर सावंत के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और मुकदमे की प्रक्रिया शुरू हुई।

हालांकि मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष ने अभियोजन की पूरी कहानी पर सवाल खड़े किए। बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत को बताया कि सावंत केवल एक लिपिकीय कर्मचारी थे और उनके पास न तो प्रमाणित प्रतियां जारी करने का अंतिम अधिकार था और न ही किसी दस्तावेज को स्वीकृत करने की प्रशासनिक शक्ति। ऐसे में यह आरोप कि उन्होंने दस्तावेज जारी करने के बदले रिश्वत मांगी, तर्कसंगत नहीं माना जा सकता।

बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि जिस धनराशि को रिश्वत बताया गया, वह संभवतः दस्तावेजों से संबंधित आधिकारिक शुल्क हो सकती थी। अदालत ने इस पहलू पर भी गंभीरता से विचार किया। सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरओसी कार्यालय में दस्तावेज प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से जमा कराया जाता था। ऐसे में धनराशि की प्रकृति को लेकर भी संदेह बना रहा।

मामले में प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभियोजन पक्ष रिश्वत मांगने के आरोप को संदेह से परे सिद्ध नहीं कर पाया। न्यायालय ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में केवल धनराशि की बरामदगी पर्याप्त नहीं होती, बल्कि यह भी साबित होना चाहिए कि आरोपी ने अवैध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से रिश्वत मांगी और स्वीकार की थी।

विधान परिषद चुनाव से पहले एमवीए में सीटों पर सहमति, 17 सीटों के बंटवारे ने तय की सियासी दिशा

मुंबई। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी (एमवीए) ने लंबे मंथन और कई दौर की बैठकों के बाद आखिरकार सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। आगामी 18 जून को होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के बीच 17 सीटों के वितरण पर बनी सहमति को विपक्षी गठबंधन की बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। सीटों के बंटवारे के साथ ही एमवीए ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि गठबंधन में मतभेदों की चर्चाओं के बावजूद तीनों दल चुनावी मैदान में पूरी एकजुटता के साथ उतरने को तैयार हैं।

मुंबई में आयोजित महत्वपूर्ण समन्वय बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने सीट बंटवारे की आधिकारिक जानकारी दी। उनके अनुसार 17 सीटों में से कांग्रेस को सबसे अधिक 8 सीटें मिली हैं, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें आवंटित की गई हैं। इस समझौते को गठबंधन के भीतर संतुलन बनाए रखने वाला फार्मूला माना जा रहा है।

सीटों के वितरण पर नजर डालें तो कांग्रेस को विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण सीटें मिली हैं। इनमें चंद्रपुर-गडचिरोली, यवतमाल, भंडारा-गोंदिया, नागपुर, अमरावती, अहिल्यानगर, सोलापुर तथा धाराशिव-बीड-लातूर जैसी सीटें शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन क्षेत्रों में कांग्रेस का परंपरागत जनाधार अपेक्षाकृत मजबूत रहा है और पार्टी इन्हीं समीकरणों के आधार पर चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। विशेष

रूप से विदर्भ की सीटों को लेकर कांग्रेस काफी आशावादी दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं।

उधर, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को रत्नागिरी, जलगांव, परभणी-हिंगोली, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड और नाशिक जैसी सीटें मिली हैं। इन क्षेत्रों में शिवसेना का पारंपरिक प्रभाव रहा है और पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि स्थानीय स्तर पर मजबूत संगठनात्मक ढांचे का लाभ चुनाव में मिलेगा। शिवसेना के नेताओं का मानना है कि विधान परिषद चुनाव केवल सीट जीतने की लड़ाई नहीं है, बल्कि राज्य की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता और जनसमर्थन साबित करने का भी अवसर है। वहीं शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पुणे, ठाणे और सातारा-सांगली जैसी तीन महत्वपूर्ण सीटें मिली हैं। ये क्षेत्र लंबे समय से राकांपा की राजनीतिक ताकत के केंद्र माने जाते रहे हैं। विशेष रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में पार्टी का मजबूत आधार होने के कारण इन सीटों को राकांपा के लिए सुरक्षित माना जा रहा है। गठबंधन के नेताओं का कहना है कि सीटों का यह वितरण राजनीतिक ताकत, स्थानीय परिस्थितियों और जीत की संभावनाओं को ध्यान में रखकर किया गया है।

यशवंतराव चव्हाण सभागृह में आयोजित बैठक के दौरान केवल सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ, बल्कि चुनावी रणनीति, संभावित उम्मीदवारों और प्रचार अभियान को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार तीनों दलों ने इस बात पर सहमति जताई कि भाजपा और महायुति के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जाएगा तथा स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा से बचा जाएगा। गठबंधन नेताओं का मानना है कि यदि विपक्षी वोटों का विभाजन रोका गया तो विधान परिषद चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को कड़ी चुनौती दी जा सकती है।

बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में धनबल का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को प्रभावित करने के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। सपकाल ने आरोप लगाया कि चुनाव को निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बजाय आर्थिक शक्ति के प्रदर्शन में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी इस प्रवृत्ति के खिलाफ संघर्ष करेगी और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए चुनाव मैदान में उतरेगी।

एमवीए नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विपक्षी मतदाताओं और स्थानीय प्रतिनिधियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भाजपा ने ऐसे आरोपों को खारिज करते हुए विपक्ष पर हार के डर से बहाने बनाने का आरोप लगाया है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि विधान परिषद चुनाव भले ही प्रत्यक्ष जनमत से नहीं होते, लेकिन इनके परिणाम राज्य की राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

महाविकास आघाड़ी ने इस चुनाव को केवल सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र, संविधान और महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपराओं की रक्षा का अभियान बताया है। गठबंधन के नेताओं का कहना है कि वे राज्य में विपक्ष की आवाज को मजबूत करने और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने के उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा और महायुति इस चुनाव को अपनी नीतियों और विकास कार्यों पर जनता की मुहर के रूप में प्रस्तुत कर रही है।

अब जबकि सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है, तीनों दल जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुनावी अभियान को गति देंगे। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि किन सीटों पर मुकाबला सबसे अधिक रोचक होगा और कौन से क्षेत्र चुनाव परिणामों में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि 18 जून का विधान परिषद चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में नई सियासी तस्वीर उभारने वाला साबित हो सकता है, जहां एक ओर महाविकास आघाड़ी अपनी एकजुटता की परीक्षा देगी तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ गठबंधन अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने की कोशिश करेगा।

संपादकीय

सिद्धारमैया के इस्तीफे से नए दौर की शुरुआत

कभी भाजपा के गढ़ रहे कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता वापसी में डी.के. शिवकुमार की बड़ी भूमिका मानी जाती रही है। जिस ऊर्जा व तेवरों से, उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस सगंठन व कार्यकर्ताओं को एकजुट करके लड़ाया, उससे उम्मीद थी सरकार बनने के बाद उनकी ही ताजपोशी होगी। वे न केवल संगठन के सूत्रधार ही थे, बल्कि उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों का त्रास भी झेला था। बहरहाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से सिद्धारमैया के इस्तीफे ने अब तक उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभाते रहे डी.के. शिवकुमार की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। देर से ही सही कांग्रेस हाईकमान ने उस चूक को दुरुस्त किया है, जिसके चलते कई राज्यों में नेतृत्व चयन की गफलत की बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी थी। बहरहाल, 77 वर्षीय सिद्धारमैया की सरकार ने पिछले ही सप्ताह अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे किए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा है। हालांकि, राज्यभर में उनके समर्थकों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन संकेत देते हैं कि इस नेतृत्व परिवर्तन को एक सामान्य बदलाव के रूप में नहीं देखा जा सकता। कयास लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा बदलाव मई 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद सत्ता साझाकरण की बारी-बारी से व्यवस्था की अटकलों को बल देता प्रतीत होता है। हालांकि, कांग्रेस पार्टी इस बात से इनकार करती है लेकिन ऐसा लगता है कि सत्ता के बंटवारे के इस समझौते ने कर्नाटक में पार्टी की आंतरिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। इस बदलाव के लिये लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे डी.के. शिवकुमार अब इस प्रतिष्ठित पद के लिये और इंतजार करते नहीं दिखायी दे रहे थे। जाहिरा तौर पर पहले की तरह वर्ष 2028 के चुनावी संग्राम के लिये पार्टी को तैयार करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। उन्हें अगले दो वर्षों में राज्य में सुशासन को प्राथमिकता देनी होगी। इस बात को कुछ देर से ही सही, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने महसूस तो किया है।

राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व को देर-सवेर अहसास होने लगा था कि जिस कर्नाटक को भाजपा दक्षिण का द्वार बताकर विगत में वर्चस्व बना चुकी है, वहां पार्टी को नेतृत्व-द्वंद्व का नुकसान हो सकता था। जिसकी पूर्ति तेज-तर्रार डी.के. शिवकुमार जैसे नेतृत्व से ही संभव हो सकती है। निर्विवाद रूप से वे अपेक्षाकृत कम उम्र के जुझारू राजनेता के रूप में पहचान रखते हैं। उन्हें कुशल चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाना जाता रहा है। बहरहाल, अब कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य में पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और दलितों का समर्थन बरकरार रखना है। माना जाता है कि इन वर्गों में सिद्धारमैया की खासी मजबूत पकड़ रही है। वहीं दूसरी ओर निवर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र की राजनीति में भूमिका को स्वीकार करने के लिये दिए गए प्रस्ताव पर अनिच्छा जताने ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। बहरहाल, इसी तरह के अनिर्णय व असमंजस की स्थिति का नुकसान विगत में कांग्रेस कई राज्यों में उठा चुकी है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 2018-23 तक पद पर बनाये रखा, जबकि उनके सहयोगी और प्रतिद्वंद्वी टीएस सिंह देव लगातार उन पर दबाव डाल रहे थे। पंजाब में, पार्टी ने साल 2022 के विधानसभा चुनावों से ठीक पांच महीने पहले कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करने के उद्देश्य से उठाया गया यह कठोर कदम कांग्रेस को बड़ा झटका दे गया था। कर्नाटक कांग्रेस के लिये दक्षिणी राज्यों में पकड़ बनाने की नीतियों की वजह से एक महत्वपूर्ण राज्य है। विगत में राज्य में भाजपा की पकड़ मजबूत रही है। यहां पार्टी का मजबूत संगठन मौजूद भी है। बहरहाल, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका यह दांव शिवकुमार और सिद्धारमैया के नेतृत्व वाले गुटों के बीच मतभेद को बढ़ाने वाला साबित न हो। बल्कि मिल-जुलकर पार्टी संगठन को मजबूती देने के प्रयास हों।

ग्रेट निकोबार परियोजना से बढ़ी चीन की बेचैनी

> ग्रेट निकोबार द्वीप, मलक्का जलडमरूमध्य के पश्चिमी प्रवेश द्वार से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित है। इस भौगोलिक निकटता के कारण, निकोबार द्वीपसमूह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच होने वाले वैश्विक व्यापार के लिए एक अत्यंत रणनीतिक समुद्री चौकी बन जाता है।

पेइचिंग के हाईतियन ज़िले में रनमिन यूनिवर्सिटी शोध के लिए प्रसिद्ध है। यहां चीनी विदेश रणनीति अध्ययन केंद्र के निदेशक जिन कैनरोंग ने अपने निजी वी-चैट अकाउंट पर प्रकाशित एक हालिया टिप्पणी में तर्क दिया, कि चीन की लंबे समय से चली आ रही 'मलाक्का दुविधा' अब और भी गंभीर होती जा रही है। चीन को डर है, कि मलाक्का जलडमरूमध्य पर उसकी भारी निर्भरता उसकी रणनीतिक कमज़ोरी बन सकती है। न्यूज़ एजेंसी रायटर्स ने अप्रैल में रिपोर्ट दी थी कि चीन के कच्चे तेल के आयात का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा मलाक्का जलडमरूमध्य से होकर गुज़रता है, जबकि यह जलडमरूमध्य वैश्विक व्यापार का लगभग 22 फीसद और समुद्री तेल का 29 प्रतिशत हिस्सा संभालता है।

जिन कैनरोंग ने लिखा कि पहले चीन की चिंताएं मुख्य रूप से अमेरिका पर केंद्रित थीं, जिसकी वैश्विक नौसैनिक पहुंच में हिंद महासागर में दिएगो गार्सिया और सिंगापुर में चांगी नौसैनिक अड्डे जैसे ठिकाने शामिल हैं। उन्होंने कहा, लेकिन अब, भारत की भूमिका बढ़ रही है। यदि भारत ग्रेट निकोबार पर अपनी उपस्थिति मज़बूत करता है, तो इससे भारत को चीन की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एक संकरे समुद्री मार्ग (चोकप्वाइंट) पर अधिक प्रभाव डालने की शक्ति मिल सकती है।

भारत सरकार द्वारा ग्रेट निकोबार द्वीप पर लगभग 10 अरब डॉलर यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से 'ग्रेट निकोबार विकास परियोजना' पर काम किया जा रहा है। इस रणनीतिक पहल का मुख्य उद्देश्य भारत के सबसे दक्षिणी छोर को एक विशाल वाणिज्यिक और सैन्य

केंद्र में बदलना है। इस महात्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य गलाथिया खाड़ी में एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह (पोर्ट), अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक नई टाउनशिप और 450 मेगावाट का गैस और सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल है। रणनीतिक रूप से मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित यह केंद्र हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों (जैसे 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स') का मुकाबला करने में भारत की नौसैनिक क्षमता को बढ़ावा देगा। इस पोर्ट के जरिए भारत अपने ट्रांस-शिपमेंट कार्गो के लिए सिंगापुर और कोलंबो जैसे विदेशी बंदरगाहों पर अपनी निर्भरता कम कर सकेगा। पूर्ण क्षमता पर, इस बंदरगाह से सालाना 1.6 करोड़ ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स (टीईयूएस) का संचालन होने का अनुमान है। भारत सरकार द्वारा 2021 में शुरू की गई यह योजना तेजी से विकास की ओर बढ़ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत वर्षा वनों के बड़े पैमाने पर कटने की आशंका को लेकर पर्यावरणविदों और मानवाधिकार समूहों की चिंता है।

प्रोफेसर जिन कैनरोंग ने चीन को तीन सुझाव दिए हैं—पहला, चीन को एक अधिक शक्तिशाली 'ब्लू-वॉटर नेवी' (गहरे समुद्र में काम करने वाली नौसेना) बनानी चाहिए। चीन को अपने विमानवाहक पोत बेड़े के विकास में तेज़ी लानी चाहिए, और चीन के सबसे नए तथा सबसे उन्नत विमानवाहक पोत 'फुचियान' को जल्द से जल्द युद्ध के लिए तैयार करना चाहिए।

दूसरा, चीन को उन मार्गों पर काम में तेज़ी लानी चाहिए जो मलाक्का को बाईपास करते हैं। जिन ने म्यांमार के पश्चिमी तट पर स्थित चीन-समर्थित गहरे समुद्र के बंदरगाह 'क्याउकप्यू', प्रस्तावित चीन-म्यांमार रेलवे, और म्यांमार से चीन के दक्षिण-पश्चिमी युन्नान प्रांत की राजधानी कुनमिंग तक जाने वाली तेल और गैस पाइपलाइनों की ओर इशारा किया। उन्होंने थाईलैंड के प्रस्तावित 'क्रा लैंड ब्रिज' का भी ज़िक्र किया—जो सड़क और रेल मार्ग के ज़रिए थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर को जोड़ने की एक योजना है—और इसे इस जलडमरूमध्य पर चीन की निर्भरता कम करने का एक और तरीका बताया। तीसरा, चीन को ताइवान मुद्दे का समाधान करना चाहिए। जिन ने तर्क दिया कि यदि पेइचिंग, ताइवान के प्रश्न को सुलझा लेता है, तो उसे पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में अपनी गतिविधियों के लिए अधिक गुंजाइश मिल जाएगी। वहां से, चीन मलक्का के पास अपने हितों की रक्षा करने की बेहतर स्थिति में होगा।

भले ही चीन और भारत सीमा पर वर्षों के तनाव के बाद अपने संबंधों को सावधानीपूर्वक स्थिर करते दिख रहे हैं, जिनकी टिप्पणी से पता चलता है, कि रणनीतिक अविश्वास अब भी कितना गहरा है। ग्रेट निकोबार परियोजना से यह भी पता चलता है कि भारत को लेकर चीन की चिंताएं अब केवल ज़मीनी सीमा तक ही सीमित नहीं हैं। भारत को अब तेज़ी से एक समुद्री प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जा रहा है, जो हिंद महासागर और दक्षिण-पूर्व एशियाई समुद्री मार्गों तक चीन की पहुंच को प्रभावित कर सकता है, और भारत संभवतः पेइचिंग की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन-रेखाओं में से एक के पास अपना प्रभाव बढ़ा सकता है।

ग्रेट निकोबार द्वीप, मलक्का जलडमरूमध्य के पश्चिमी प्रवेश द्वार से लगभग 150 किलोमीटर (90 नॉटिकल माइल) उत्तर-पश्चिम में स्थित है। इस भौगोलिक निकटता के कारण, निकोबार द्वीपसमूह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच होने वाले वैश्विक व्यापार के लिए एक अत्यंत रणनीतिक समुद्री चौकी बन जाता है। अंडमान सागर के रास्ते मलक्का जलडमरूमध्य में प्रवेश करने या उससे बाहर निकलने के लिए जहाज़ों को 'सिक्स डिग्री चैनल' से होकर गुज़रना पड़ता है, जिससे वैश्विक शिपिंग मार्ग सीधे भारतीय क्षेत्र के निकट आ जाते हैं। इस निकटता के कारण, भारत इस महत्वपूर्ण मार्ग को सुरक्षित रखने और उस पर निगरानी रखने के लिए अपनी नौसैनिक अवसंरचना का बड़े पैमाने पर विस्तार कर रहा है, और ग्रेट निकोबार पर एक विशाल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का निर्माण कर रहा है।

सिंगापुर जलडमरूमध्य के फ़िलिप्स चैनल में अपने सबसे संकरे बिंदु पर, मलाक्का जलडमरूमध्य की चौड़ाई सिर्फ़ 1.7 मील (2.7 किमी) है; इससे एक प्राकृतिक रुकावट पैदा होती है, साथ ही जहाज़ों के टकराने, ज़मीन से टकराने या तेल फैलने का भी खतरा बना रहता है। सालों से, यह जलडमरूमध्य समुद्री डकैती और व्यापारिक जहाजों पर हमलों का एक बड़ा केंद्र रहा है।

टैंकर ट्रैकर 'वोरटेक्सा' के आंकड़ों के अनुसार, 'यह संकरा और भीड़भाड़ वाला जलमार्ग पेइचिंग के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि चीन के समुद्री रास्ते से होने वाले कच्चे तेल के आयात का लगभग 75 फीसद हिस्सा इसी रास्ते से मध्य पूर्व और अफ्रीका से होकर गुजरता है।' होनोलुलु स्थित ईस्ट-वेस्ट सेंटर की एडजंक्ट फेलो, निलंथी समरनायके ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को भारत की 20 साल पुरानी ज़रूरत का सबसे नया अपडेट बताया। समरनायके ने कहा, 'अब जो बात अलग है, वह यह है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर अब ज़्यादा तेज़ी दिख रही है।' निश्चित रूप से अपनी ऊर्जा सुरक्षा और चीन पर दबाव बनाये रखने के लिए निकोबार पोर्ट का विकास आवश्यक है। मगर, इस जगह वर्षा वनों के काटे जाने का विकल्प केंद्र सरकार ने क्या ढूंढ़ा है, उसे भी एड्रेस करना उतना ही ज़रूरी है।

प्रेरणा

जब भगवान भी भावुक हो उठेः हनुमान के प्रेम में डूबे श्रीराम

लंका की धरती पर उस समय भय, अहंकार और अत्याचार का साम्राज्य था। रावण की अशोक वाटिका में माता सीता विरह की अग्नि में तप रही थीं। चारों ओर राक्षसियों का पहरा, रावण की धमकियाँ और अंतहीन पीड़ा के बीच भी उनके हृदय में केवल एक ही नाम धड़क रहा था—राम। दूसरी ओर प्रभु श्रीराम वन-वन भटकते हुए अपनी प्रिय सीता की खोज में व्याकुल थे। उनके नेत्रों की शांति खो चुकी थी और हृदय में विरह का अथाह सागर उमड़ रहा था। तभी उस कठिन समय में पवनपुत्र हनुमान आशा की किरण बनकर आगे आए। उन्होंने न केवल समुद्र लांघा, बल्कि अपने अद्भुत साहस, बुद्धि और भक्ति से वह कार्य कर दिखाया जिसे असंभव माना जा रहा था।

अशोक वाटिका में जब हनुमान ने पहली बार माता सीता को देखा, तो उनकी आँखें नम हो उठीं। एक महारानी, जो कभी अयोध्या के महलों की शोभा थीं, आज वृक्ष के नीचे अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने प्रभु का स्मरण कर रही थीं। हनुमान ने अत्यंत विनम्रता से श्रीराम की मुद्रिका उन्हें दी। मुद्रिका देखते ही सीता की आँखों में वर्षों बाद आशा की चमक लौटी। उन्हें विश्वास हो गया कि उनके राम उन्हें अवश्य लेने आएंगे। उस समय माता सीता ने अपने सिर से चूड़ामणि उतारी और हनुमान को देते हुए कहा कि इसे प्रभु श्रीराम को सौंप देना। यह केवल एक आभूषण नहीं था, बल्कि उनके प्रेम, विश्वास और प्रतीक्षा का प्रतीक था।

हनुमान जब लंका से लौटे, तब वानर सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। सभी जानते थे कि वे कोई शुभ समाचार लेकर आए हैं। परंतु सबसे अधिक व्याकुल स्वयं श्रीराम थे। जैसे ही हनुमान उनके सामने पहुँचे, उन्होंने अत्यंत विनम्रता से माता सीता का संदेश सुनाया। फिर अपने दोनों हाथों से वह चूड़ामणि श्रीराम को अर्पित कर दी। उस क्षण जैसे समय ठहर गया। श्रीराम ने कांपते हाथों से चूड़ामणि को ग्रहण किया। उनकी आँखें भर आईं। कुछ क्षणों तक वे उसे देख भी नहीं सके। उनके मन में विवाह का वह पावन दृश्य जीवित हो उठा, जब मिथिला में जनकनंदिनी सीता ने उन्हें पति रूप में स्वीकार किया था। वही चूड़ामणि आज विरह और पीड़ा का संदेश लेकर उनके हाथों में थी।

श्रीराम का हृदय करुणा से पिघल उठा। उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी प्रिय सीता कितने कष्टों में हैं। उनका मन बार-बार अशोक वाटिका की ओर दौड़ रहा था। वे उस चूड़ामणि को अपने हृदय से लगाकर मौन हो गए। उनके नेत्रों से आँसू बहने लगे। वह दृश्य इतना भावुक था कि वहाँ उपस्थित वानर सेना भी स्तब्ध रह गई। भगवान कहलाने वाले श्रीराम उस समय केवल एक विरही पति थे, जो अपनी पत्नी के दुःख से टूट रहे थे।

फिर उनकी दृष्टि हनुमान पर पड़ी। सामने खड़ा वह वानर केवल एक सेवक नहीं था। वह प्रेम, निष्ठा और समर्पण की मूर्ति था। उसने अपने प्रभु के लिए असंभव को संभव कर दिया था। समुद्र लांघना, लंका में प्रवेश करना, रावण के सैनिकों से लड़ना, अशोक वाटिका उजाड़ देना और फिर सुरक्षित लौट आना—यह सब कोई साधारण कार्य नहीं था। परंतु हनुमान के चेहरे पर विजय का गर्व नहीं था। वे अत्यंत विनम्र भाव से केवल अपने प्रभु के चरणों को निहार रहे थे।

यही हनुमान की महानता थी। वे अपनी शक्ति को कभी अपनी नहीं मानते थे। वे जानते थे कि उनका हर सामर्थ्य केवल रामकृपा का परिणाम है। इसलिए उनमें अहंकार का नाम तक नहीं था। संसार में अक्सर व्यक्ति थोड़ा-सा कार्य करके भी प्रशंसा चाहता है, लेकिन हनुमान ने इतना महान कार्य करके भी स्वयं को केवल "रामदूत" कहा। उनके भीतर केवल सेवा का भाव था, अधिकार का नहीं।

श्रीराम यह सब देखकर भाव-विभोर हो उठे। उन्होंने सोचना शुरू किया कि हनुमान को क्या उपहार दिया जाए। एक राजा अपने सेवक को धन दे सकता है, पद दे सकता है, सम्मान दे सकता है, लेकिन हनुमान की सेवा इन सब से कहीं ऊपर थी। पूरे ब्रह्मांड का वैभव भी उस भक्ति के सामने छोटा था। श्रीराम को लगा कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, जो हनुमान के प्रेम और त्याग का मूल्य चुका सके। तभी वे उठे और हनुमान के पास जाकर अत्यंत कोमल स्वर में बोले, "हे हनुमान! तुमने जो कार्य किया है, उसका प्रतिदान देना मेरे लिए संभव नहीं है। तुमने मेरे लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। इस संसार में ऐसा कोई उपहार नहीं, जो तुम्हारी सेवा के बराबर हो। इसलिए मैं तुम्हें अपना सर्वस्व देता हूँ।" इतना कहकर श्रीराम ने हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया।

वह केवल एक आलिंगन नहीं था, बल्कि भक्ति की सर्वोच्च उपलब्धि थी। जैसे ही हनुमान श्रीराम के वक्ष से लगे, उनके भीतर अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। उन्हें लगा कि उनके शरीर की सीमाएँ समाप्त हो रही हैं। उनका मन, प्राण और चेतना सब कुछ राममय हो रहा है। उस क्षण भक्त और भगवान के बीच का भेद मिट गया। हनुमान को अनुभव हुआ कि वे स्वयं राम में विलीन हो गए हैं। यह प्रसंग केवल रामायण की कथा नहीं, बल्कि भक्ति का सबसे गहरा दर्शन है। जब कोई भक्त अपने भीतर से अहंकार मिटाकर केवल प्रेम और सेवा को अपनाता है, तब भगवान स्वयं उसके हो जाते हैं। हनुमान ने कभी अपने लिए कुछ नहीं माँगा। उन्हें केवल अपने प्रभु की प्रसन्नता चाहिए थी। यही कारण है कि संसार में जितना प्रेम श्रीराम ने हनुमान को दिया, उतना किसी और को नहीं मिला।

आज भी जब भक्त इस प्रसंग को सुनते हैं, तो उनकी आँखें नम हो जाती हैं। यह कथा सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए केवल पूजा-पाठ ही पर्याप्त नहीं, बल्कि निष्काम प्रेम और सेवा की आवश्यकता होती है। भगवान बाहरी वैभव से नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। हनुमान का जीवन इसी सत्य का प्रमाण है।

श्रीराम और हनुमान का यह दिव्य संबंध मानवता को यह संदेश देता है कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ दूरी समाप्त हो जाती है। वहाँ भक्त और भगवान अलग नहीं रहते। वहाँ केवल एक दिव्य एकता रह जाती है, जिसमें समर्पण भी है, करुणा भी है और अनंत आनंद भी। यही कारण है कि राम और हनुमान का यह प्रसंग युगों-युगों तक भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण बना रहेगा।

किसानों के लिए कुछ भी कर जाते हैं PM Modi

किसानों के हितों की रक्षा और देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाए रखना मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट मानना है कि किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, इसलिए जरूरत पड़ने पर सरकार इसके लिए खजाना खोलने से भी पीछे नहीं हटती। हम आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर खाद की आपूर्ति और कीमतों पर दबाव बढ़ा है, लेकिन केंद्र सरकार ने समय रहते कई महत्वपूर्ण कदम उठाकर यह सुनिश्चित करने की तैयारी शुरू कर दी है कि खरीफ और रबी मौसम में किसानों को खाद की कमी का सामना न करना पड़े। वैकल्पिक परिवहन मार्गों की तलाश, अतिरिक्त आयात, बढ़ती सब्सिडी का बोझ उठाने की तैयारी और सक्रिय कूटनीतिक प्रयास इस बात का प्रमाण हैं कि किसानों की जरूरतों को पूरा करना सरकार की सबसे बड़ी चिंता है। रिपोर्टों के मुताबिक, पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद भारत आने वाले खाद से लदे 17 जहाज फारस की खाड़ी क्षेत्र में फंस गए हैं। इन जहाजों के अटकने से देश में खाद आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक वैकल्पिक योजना पर काम शुरू किया है। इसके तहत संबंधित बंदरगाहों पर जहाजों के पहुंचने के बाद खाद को सड़क मार्ग से लगभग 1200 किलोमीटर दूर सऊदी अरब के यनबू बंदरगाह तक पहुंचाया जाएगा। वहां से इसे फिर समुद्री मार्ग के जरिए भारतीय बंदरगाहों तक लाने की योजना बनाई जा रही है। यद्यपि यह मार्ग लंबा है और इसमें अधिक समय लगेगा, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इसे सबसे व्यवहारिक विकल्प माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार खाद विभाग ने मंत्रियों के एक अनौपचारिक समूह को इस योजना की जानकारी दी है। अधिकारियों का मानना है कि जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित होने के कारण सीधे मार्ग से आपूर्ति फिलहाल संभव नहीं है। देरी के कारण 60 से 70 दिनों तक अतिरिक्त समय लग सकता है, जिससे लागत भी बढ़ेगी। हालांकि सरकार का मानना है कि खरीफ मौसम के दौरान किसानों को खाद की उपलब्धता बनाए रखने के लिए यह अतिरिक्त प्रयास जरूरी है। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि यदि संघर्ष लंबा खिंचता है तो इसका असर रबी फसलों की बुआई पर भी पड़ सकता है।

इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत ने खाद आयात की दिशा में भी बड़े कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने 17 लाख टन यूरिया के आयात के लिए नया वैश्विक निविदा आमंत्रित किया है। सरकारी क्षेत्र की राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने पश्चिमी और पूर्वी तटों के लिए अलग-अलग मात्रा में आयात प्रस्ताव मांगे हैं। इन खेपों को जुलाई के तीसरे सप्ताह तक रवाना करने की योजना बनाई गई है, ताकि धान, मक्का और सोयाबीन जैसी प्रमुख खरीफ फसलों की बुआई से पहले पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जा सके। हम आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया आयातक देश है और ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया का संघर्ष प्राकृतिक गैस तथा अमोनिया जैसी प्रमुख कच्ची सामग्रियों की आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है, तब मोदी सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय दिया है। इससे पहले अप्रैल में भी 25 लाख टन यूरिया आयात के लिए निविदा जारी की गई थी। वैश्विक स्तर पर आपूर्ति बाधित होने और कीमतों में वृद्धि के बावजूद सरकार लगातार अतिरिक्त खरीद और भंडारण की नीति पर काम कर रही है।

हम आपको यह भी बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर केवल आपूर्ति व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा दबाव केंद्र सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर भी पड़ रहा है। खाद विभाग के नवीनतम आकलन के अनुसार यदि मौजूदा वैश्विक कीमतें बनी रहती हैं तो चालू वित्त वर्ष में खाद सब्सिडी का बोझ बढ़कर लगभग 3.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, जबकि इसके लिए बजट में केवल 1.7 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। युद्ध के बाद यूरिया की वैश्विक कीमतों में 120 प्रतिशत से अधिक, डीएपी में 38 प्रतिशत, सल्फर में 87 प्रतिशत और अमोनिया में 84 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है। रुपये की कमजोरी के कारण लागत में अतिरिक्त बढ़ोतरी भी हुई है। भारत डीएपी, पोटाश और एनपीके जैसे प्रमुख उर्वरकों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में उथल-पुथल का सीधा असर देश पर पड़ता है। इसके बावजूद केंद्र सरकार किसानों पर अतिरिक्त बोझ डालने के बजाय सब्सिडी के माध्यम से राहत देने की नीति पर कायम है। अधिकारियों का मानना है कि यदि तनाव लंबा चला तो जहाजों की सामान्य आवाजाही बहाल होने में दो से तीन महीने लग सकते हैं, जबकि तेल और गैस आपूर्ति पूरी तरह पटरी पर आने में और अधिक समय लग सकता है। ऐसे में सरकार एक ओर आपूर्ति बनाए रखने का प्रयास कर रही है तो दूसरी ओर बढ़ती लागत के बावजूद किसानों को राहत पहुंचाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की तैयारी भी कर रही है।

हम आपको यह भी बता दें कि मोदी सरकार की कूटनीति भी इस संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत ने केवल खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय रूस, मिस्र, कतर, नाइजीरिया समेत कई देशों से खाद और उससे जुड़ी आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित की है। सरकार दीर्घकालिक आपूर्ति समझौतों को बढ़ावा देने के साथ-साथ वैकल्पिक समुद्री मार्गों की भी तलाश कर रही है। इसका उद्देश्य भविष्य में किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना और आपूर्ति श्रृंखला को अधिक मजबूत बनाना है।

रिपोर्टों के मुताबिक, घरेलू उत्पादन को बनाए रखने के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। खाद कारखानों को मिलने वाली गैस की आपूर्ति को पहले के लगभग 70 से 75 प्रतिशत स्तर से बढ़ाकर करीब 90 प्रतिशत तक कर दिया गया है। इससे उत्पादन क्षमता को बनाए रखने में मदद मिली है और घरेलू बाजार में खाद की उपलब्धता को स्थिर रखा जा सका है।

अभियान

गंगा दशहरा: भारतीय संस्कृति, आस्था और प्रकृति सम्मान का दिव्य महापर्व

भारत की संस्कृति में नदियों को केवल जलधारा नहीं माना गया, बल्कि उन्हें जीवनदायिनी मां का स्वरूप दिया गया है। इन्हीं पवित्र नदियों में मां गंगा का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। हिमालय की गोद से निकलकर मैदानों को जीवन देने वाली गंगा सदियों से भारतीय सभ्यता की धड़कन रही है। इसी कारण गंगा दशहरा का पर्व केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय लोकजीवन और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना का महापर्व माना जाता है। यह पर्व उस दिव्य क्षण की स्मृति में मनाया जाता है, जब मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं और उन्होंने मानव जीवन को पवित्रता, करुणा और मुक्ति का संदेश दिया था। हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इस वर्ष यह तिथि 25 मई को प्रातः 4:30 बजे से प्रारंभ होकर 26 मई को प्रातः 5:10 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार यह पर्व 25 मई को मनाया जाएगा। विशेष बात यह है कि इस बार गंगा दशहरा सोमवार के दिन पड़ रहा है, जो भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। चूंकि गंगा भगवान शिव की जटाओं से होकर पृथ्वी पर प्रवाहित हुई थीं, इसलिए इस दिन शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। श्रद्धालु गंगा स्नान, जल अर्पण, दान-पुण्य और भगवान शिव की आराधना कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं।

गंगा अवतरण की कथा भारतीय पुराणों में अत्यंत भावपूर्ण और प्रेरणादायक रूप में वर्णित है। कहा जाता है कि सूर्यवंशी राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ का घोड़ा देवराज इंद्र द्वारा कपिल मुनि के आश्रम के समीप छिपा दिया गया। राजा सगर के साठ हजार पुत्र घोड़े की खोज करते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। उनके इस अपराध से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें श्राप देकर भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए भटकती रहीं। कई पीढ़ियों बाद राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुईं, लेकिन उनका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। शिव ने अपनी विशाल जटाओं में गंगा को धारण कर उनके वेग को नियंत्रित किया और धीरे-धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यही घटना गंगा अवतरण कहलाती है।

यह कथा केवल पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के गहरे संदेश को व्यक्त करती है। राजा भगीरथ का तप त्याग, धैर्य और लोककल्याण का प्रतीक है। उन्होंने केवल अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता के कल्याण के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया। इसी कारण आज भी किसी बड़े और कठिन कार्य को "भगीरथ प्रयास" कहा जाता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा जीवन वही है, जो दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित हो।

गंगा दशहरा को "दस प्रकार के पापों का नाश करने वाला पर्व" भी कहा जाता है। 'दश' का अर्थ दस और 'हरा' का अर्थ नष्ट करने वाला है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के दस प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि इस अवसर पर देशभर के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की विशाल भीड़ उमड़ती है। काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी और गंगासागर जैसे तीर्थस्थलों पर लाखों लोग स्नान कर पूजा-अर्चना करते हैं। श्रद्धालु दीपदान करते हैं, गंगा आरती में भाग लेते हैं और मां गंगा से सुख-समृद्धि तथा मोक्ष का आशीर्वाद मांगते हैं।

भारतीय जीवन में गंगा जल का महत्व अत्यंत विशेष माना गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हिंदू धर्म के लगभग सभी संस्कारों में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। नवजात शिशु के संस्कार से लेकर विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश और अंतिम संस्कार तक गंगा जल को पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यह विश्वास केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना का भी हिस्सा है। गांवों में आज भी लोग गंगा जल हाथ में लेकर सत्य बोलने की शपथ लेते हैं। यह गंगा के प्रति लोगों की गहरी आस्था को दर्शाता है।

भारतीय साहित्य और कला में भी गंगा का विशेष स्थान रहा है। तुलसीदास, सूरदास, कबीर और अन्य संत कवियों ने अपनी रचनाओं में गंगा की महिमा का गुणगान किया है। संस्कृत साहित्य में गंगा को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पवित्र सेतु माना गया है। लोकगीतों और भजनों में गंगा मां के रूप में पूजी जाती हैं। भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला में भी गंगा का दिव्य स्वरूप दिखाई देता है। यही कारण है कि गंगा केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक आत्मा का हिस्सा हैं।

गंगा दशहरा का पर्व भारतीय लोकजीवन में उत्सव और उल्लास का वातावरण लेकर आता है। ऋषिकेश से लेकर गंगासागर तक अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं। घाटों को दीपों और फूलों से सजाया जाता है। भजन-कीर्तन, कथा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भंडारों का आयोजन किया जाता है। लोग परिवार सहित गंगा तटों पर पहुंचकर पूजा करते हैं और सामाजिक मेलजोल का आनंद लेते हैं। यह पर्व भारतीय समाज की सामूहिक आस्था और सांस्कृतिक एकता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है।

आधुनिक समय में गंगा दशहरा का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि यह हमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। जिस गंगा को हम मां कहकर पूजते हैं, वही आज प्रदूषण, औद्योगिक कचरे, प्लास्टिक और गंदगी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण ने गंगा की निर्मलता को प्रभावित किया है। अनेक स्थानों पर गंगा का जल प्रदूषित हो चुका है, जिससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में गंगा दशहरा केवल पूजा और स्नान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह संकल्प लेने का अवसर भी होना चाहिए कि हम गंगा और अन्य नदियों की स्वच्छता बनाए रखेंगे।

पिछले कुछ वर्षों में अनेक सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और आम नागरिक गंगा सफाई अभियान चला रहे हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर घाटों की सफाई, प्लास्टिक मुक्त अभियान और जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह पहल समाज में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है। वास्तव में यदि हम गंगा को मां मानते हैं, तो केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखना भी हमारा कर्तव्य है।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गंगा दशहरा जैसे पर्व लोगों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन प्रदान करते हैं। आधुनिक जीवन में भौतिक उपलब्धियों की दौड़ इतनी तेज हो गई है कि मनुष्य प्रकृति और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दूर होता जा रहा है। ऐसे समय में गंगा दशहरा हमें यह याद दिलाता है कि जीवन केवल भौतिक सुख-सुविधाओं तक सीमित नहीं है। प्रकृति के प्रति सम्मान, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है।

गंगा का प्रवाह हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वह पर्वतों से निकलकर मैदानों, गांवों और शहरों को जीवन देती हुई समुद्र तक पहुंचती है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में निरंतर कर्म करते हुए दूसरों के लिए उपयोगी बनना चाहिए। गंगा निस्वार्थ सेवा और त्याग की प्रतीक हैं। वे बिना किसी भेदभाव के सबको जल प्रदान करती हैं। यही संदेश भारतीय संस्कृति की मूल भावना है।

गंगा दशहरा केवल धार्मिक अनुष्ठान का दिन नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा को समझने का अवसर है। यह पर्व हमें हमारी परंपराओं, प्रकृति और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ता है। यह बताता है कि नदी केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि जीवन, संस्कृति और चेतना की धारा है। मां गंगा के प्रति श्रद्धा वास्तव में प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना है। इसलिए गंगा दशहरा भारतीय संस्कृति में केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि मानव और प्रकृति के मधुर संबंध का जीवंत उत्सव है, जो हमें करुणा, सेवा, पवित्रता और पर्यावरण संरक्षण का अमूल्य संदेश देता है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

बंदरगाहों में फंसा 250 करोड़ का धागा, सूरत के टेक्सटाइल उद्योग पर गहराया संकट

सूरत। देश की टेक्सटाइल राजधानी कहे जाने वाले सूरत का वस्त्र उद्योग इन दिनों एक बड़े संकट से जूझ रहा है। विदेशी बाजारों से आयात किया गया करोड़ों रुपये मूल्य का विशेष गुणवत्ता वाला यार्न (धागा) कानूनी अड़चनों के कारण गुजरात और महाराष्ट्र के प्रमुख बंदरगाहों पर फंस गया है। गुजरात हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद कस्टम विभाग ने इन कंटेनरों की क्लियरेंस रोक दी है, जिसके चलते व्यापारियों, बुनकरों और उद्योग से जुड़े हजारों लोगों के सामने गंभीर आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई है। उद्योग जगत का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो इसका असर केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्पादन, रोजगार और निर्यात पर भी दिखाई देगा।

उद्योग सूत्रों के अनुसार मुंबई के न्हावा शेवा पोर्ट और सूरत के हजीरा पोर्ट पर लगभग एक हजार कंटेनर रुके हुए हैं। इनमें करीब 250 करोड़ रुपये मूल्य का आयातित धागा रखा हुआ है, जिसकी टेक्सटाइल उद्योग में भारी मांग है। बताया जा रहा है कि दोनों बंदरगाहों पर लगभग 500-500 कंटेनर फंसे हुए हैं। यह धागा चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया और अन्य देशों से आयात किया गया था, ताकि सूरत के कपड़ा उद्योग को उच्च गुणवत्ता वाला कच्चा माल उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन कानूनी विवाद के कारण यह सामग्री अब तक उद्योगों तक नहीं पहुंच पाई है।

स्थिति को और गंभीर बनाते हुए स्थानीय स्पिनिंग कंपनियों ने पिछले दस दिनों में धागे की कीमतों में 15 से 20 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी कर दी है। इससे कपड़ा निर्माताओं और बुनकरों की उत्पादन लागत बढ़ गई है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि आयातित धागे की उपलब्धता रुकने से बाजार में कृत्रिम कमी पैदा हो गई है, जिसका सीधा लाभ कुछ स्थानीय उत्पादकों को मिल रहा है, जबकि हजारों छोटे और मध्यम उद्योग प्रभावित हो रहे हैं।

इस विवाद की जड़ केंद्र सरकार द्वारा जारी वह अधिसूचना है, जिसके तहत विशेष गुणवत्ता वाले यार्न के आयात की अनुमति दी गई थी। सरकार का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप मजबूत बनाना था। अनुमति मिलने के बाद सूरत के व्यापारियों ने विदेशों में बड़े पैमाने पर ऑर्डर दिए, अग्रिम भुगतान किए और बैंकों के माध्यम से लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर माल मंगवाया। जब तक माल भारत पहुंचा, तब तक मामला अदालत में पहुंच चुका था और हाई कोर्ट के स्टे आदेश ने पूरे आयात को रोक दिया।

जानकारी के अनुसार देश की पांच बड़ी स्पिनिंग कंपनियों ने इस सरकारी निर्णय को अदालत में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि आयात की अनुमति से घरेलू उत्पादकों को नुकसान होगा। दूसरी ओर यार्न व्यापारियों का कहना है कि यह कदम प्रतिस्पर्धा को रोकने और बाजार पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश है। उनका आरोप है कि अदालत में उनकी बात सुने बिना एकतरफा आदेश मिलने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

कंटेनरों के बंदरगाहों पर रुके रहने से व्यापारियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी बढ़ गया है। हर दिन डेमरेज और डिटेंशन शुल्क के रूप में लाखों रुपये का भुगतान करना पड़ रहा है। कई व्यापारियों का कहना है कि यदि स्थिति लंबी खिंची तो उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। कुछ छोटे आयातकों के लिए यह स्थिति अस्तित्व के संकट जैसी बनती जा रही है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सूरत के प्रमुख यार्न व्यापारियों ने 'द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री' (एसजीसीसीआई) से हस्तक्षेप की मांग की है। व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने चैंबर को बताया कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो उत्पादन इकाइयों में कच्चे माल की कमी हो जाएगी, जिससे कपड़ा उत्पादन प्रभावित होगा और हजारों श्रमिकों की नौकरियों पर भी खतरा मंडराने लगेगा।

चैंबर के अध्यक्ष अशोक जीरावाला ने भी उद्योग की चिंताओं को उचित बताते हुए कहा कि जिन कंटेनरों का आयात वैध सरकारी अनुमति के आधार पर किया गया है, उन्हें मानवीय और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए जल्द रिलीज किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि उद्योग और रोजगार दोनों को बचाने के लिए संबंधित पक्षों को शीघ्र समाधान निकालना होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि सूरत का टेक्सटाइल उद्योग केवल गुजरात ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। लाखों लोगों की आजीविका इस उद्योग से जुड़ी हुई है। ऐसे में आयातित धागे पर लगी रोक यदि लंबे समय तक जारी रहती है, तो इसका असर उत्पादन, निर्यात, रोजगार और पूरे वस्त्र बाजार पर पड़ सकता है। उद्योग जगत अब अदालत और सरकार दोनों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है कि जल्द कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे व्यापारिक गतिविधियां सामान्य हो सकें और सूरत का टेक्सटाइल उद्योग एक बड़े संकट से उबर सके।

गुलदस्तों से आगे बढ़कर समाज सेवा की मिसाल

सूरत। राजनीति और सार्वजनिक जीवन में अक्सर पदभार ग्रहण करने के बाद नेताओं का स्वागत फूलों के महंगे गुलदस्तों, मालाओं और स्मृति चिह्नों से किया जाता है। लेकिन सूरत महानगरपालिका की नई मेयर मायाबेन मावाणी ने इस परंपरा से अलग हटकर एक ऐसी पहल की है, जिसने न केवल लोगों का ध्यान आकर्षित किया है बल्कि जनसेवा और सामाजिक जिम्मेदारी का एक नया संदेश भी दिया है। पद संभालते ही उन्होंने अपने समर्थकों, शुभचिंतकों और नागरिकों से अपील की कि वे उन्हें फूलों के बुके भेंट करने के बजाय किताबें, नोटबुक, पेन और साड़ियां दें, ताकि इन वस्तुओं का उपयोग समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया जा सके।

सूरत, जो अपनी व्यापारिक पहचान के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता और जनहितकारी पहलों के लिए भी जाना जाता है, वहां मेयर की इस सोच को व्यापक समर्थन मिला। शुक्रवार को मेयर कार्यालय में बधाई देने पहुंचे लोगों ने पारंपरिक गुलदस्तों के स्थान पर बड़ी संख्या में शैक्षणिक सामग्री और साड़ियां भेंट कीं। कार्यालय का दृश्य भी सामान्य राजनीतिक आयोजनों से अलग

दिखाई दिया, जहां फूलों के ढेर की जगह किताबों, कॉपियों और अन्य उपयोगी वस्तुओं का संग्रह नजर आया। मेयर ने इन उपहारों को स्वीकार करने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यों की शुरुआत भी की और विभिन्न फाइलों पर हस्ताक्षर कर अपने कार्यकाल का औपचारिक शुभारंभ किया।

मेयर कार्यालय के अनुसार प्राप्त सामग्री को सीधे समाज के जरूरतमंद वर्गों तक पहुंचाया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों, फुटपाथों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले विद्यार्थियों को नोटबुक, किताबें और पेन वितरित किए जाएंगे, ताकि उनकी शिक्षा में सहयोग मिल सके। वहीं भेंट में मिली साड़ियों को वृद्धाश्रमों में रहने वाली निराश्रित और जरूरतमंद महिलाओं को सम्मानपूर्वक प्रदान किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य केवल दान देना नहीं, बल्कि समाज के उन वर्गों तक मदद पहुंचाना है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

मायाबेन मावाणी ने बताया कि इस पहल के पीछे एक बेहद भावुक अनुभव जुड़ा हुआ है। मेयर बनने के बाद जब वह पहली बार घर लौट रही थीं, तब उनकी नजर सड़क किनारे अपनी मां का हाथ पकड़े एक गरीब बच्चे पर पड़ी। बच्चे के चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, लेकिन उसके जीवन की कठिनाइयां भी साफ दिखाई दे रही थीं। उसी क्षण उनके मन में विचार आया कि स्वागत में मिलने वाले महंगे गुलदस्ते कुछ ही घंटों में मुरझाकर कूड़ेदान में चले जाते हैं, जबकि उसी धन से किसी बच्चे के हाथ में किताब पहुंचाई जाए तो उसका भविष्य बदल सकता है।

उन्होंने कहा कि समाज में छोटे-छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। यदि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग स्वागत और सम्मान की पारंपरिक परंपराओं को जनहित से जोड़ दें तो इससे हजारों जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंच सकता है। उनका मानना है कि किसी बच्चे के हाथ में किताब देना या किसी जरूरतमंद महिला को सम्मानपूर्वक साड़ी भेंट करना, फूलों के बुके प्राप्त करने से कहीं अधिक संतोष देता है।

मेयर की इस पहल को शहर के सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और आम नागरिकों ने भी सराहा है। कई लोगों का कहना है कि यदि अन्य जनप्रतिनिधि भी इसी तरह की पहल करें तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन की एक नई लहर शुरू हो सकती है। सूरत में यह कदम केवल एक प्रतीकात्मक निर्णय नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे जनप्रतिनिधियों की सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशील नेतृत्व के उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक पदों पर बैठने वाले लोगों से अक्सर विकास और प्रशासनिक कार्यों की अपेक्षा की जाती है, लेकिन मायाबेन मावाणी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत यह संदेश देकर की है कि जनसेवा केवल योजनाओं और घोषणाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के प्रति संवेदनशीलता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उनकी यह पहल न केवल सूरत बल्कि देश के अन्य शहरों के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण बन सकती है, जहां सम्मान के प्रतीकों को समाज कल्याण के साधनों में बदला जा सकता है।

बचपन पर कारोबार का बोझ: सूरत में बाल मजदूरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 23 बच्चे मुक्त

सूरत। हीरा और टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध सूरत शहर में एक बार फिर बाल मजदूरी का चिंताजनक चेहरा सामने आया है। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत वराछा क्षेत्र में की गई बड़ी कार्रवाई ने यह उजागर कर दिया कि आर्थिक मजबूरियों और लालच के कारण आज भी कई मासूम बच्चों का बचपन कारखानों की चारदीवारी में कैद हो रहा है। जिला टास्क फोर्स द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में एक हॉट फिक्सिंग यूनिट से 23 बच्चों को मुक्त कराया गया, जो लंबे समय से जोखिमभरे कार्यों में लगे हुए थे। इस कार्रवाई के बाद न केवल बाल श्रम के खिलाफ प्रशासन की सख्ती सामने आई है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि आखिर कानूनों और जागरूकता अभियानों के बावजूद बच्चों से मजदूरी कराने का सिलसिला क्यों नहीं रुक पा रहा है।

जानकारी के अनुसार सूरत के वराछा इलाके की हरिधाम सोसाइटी में संचालित एक हॉट फिक्सिंग यूनिट में बड़ी संख्या में बच्चों के काम करने की सूचना प्रशासन को मिली थी। शिकायत के आधार पर जिला टास्क फोर्स ने संयुक्त अभियान चलाया। इस अभियान में श्रम विभाग, सूरत महानगरपालिका, फैक्टरी निरीक्षण विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, 1098 चाइल्डलाइन, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU), शी-टीम तथा सामाजिक संस्था 'प्रयास' के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने जब यूनिट पर छापा मारा तो वहां काम कर रहे बच्चों को देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए।

कार्रवाई के दौरान कुल 23 बच्चों को मुक्त कराया गया। इनमें 12 लड़के और 11 लड़कियां शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार लड़कों में 11 किशोर और एक बाल मजदूर जबकि लड़कियों में आठ किशोरियां और तीन बाल मजदूर शामिल हैं। सभी बच्चों की उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच बताई गई है। इनमें अधिकांश बच्चे गुजरात और राजस्थान के विभिन्न जिलों से संबंधित हैं, जिन्हें रोजगार का झांसा देकर या आर्थिक मजबूरी के कारण यहां काम पर लगाया गया था। जांच में यह तथ्य सामने आया कि ये बच्चे पिछले एक से दो महीनों से नियमित रूप से यूनिट में कार्य कर रहे थे। उन्हें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार काम करना पड़ता था। इसके बदले उन्हें प्रतिमाह 5 हजार से 10 हजार रुपये तक का भुगतान किया जाता था। अधिकारियों ने बताया कि जिस हॉट फिक्सिंग कार्य में बच्चों को लगाया गया था, वह जोखिमभरा माना जाता है क्योंकि इसमें गर्म मशीनों और औद्योगिक उपकरणों का उपयोग होता है। ऐसे कार्यों में बच्चों की सुरक्षा को गंभीर खतरा रहता है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

सबसे गंभीर बात यह रही कि यूनिट संचालकों के पास बच्चों की उम्र और पहचान से संबंधित कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। जब अधिकारियों ने बच्चों के नियुक्ति रिकॉर्ड और आयु प्रमाण मांगे तो संचालक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इससे संदेह और गहरा गया कि बच्चों को अवैध रूप से काम पर रखा गया था। प्रशासन ने तत्काल सभी बच्चों को वहां से हटाकर सुरक्षित संरक्षण में लेने का निर्णय किया।

रेस्क्यू के बाद सभी बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। फिलहाल लड़कों को कतारगाम स्थित वी.आर. पोपावाला चिल्ड्रन्स होम और लड़कियों को रांदेर स्थित गर्ल्स चिल्ड्रन्स होम में सुरक्षित रखा गया है। वहां उनकी देखभाल, परामर्श और पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला बाल संरक्षण इकाई बच्चों के परिवारों, उनके मूल निवास स्थान और आयु संबंधी दस्तावेजों की जांच कर रही है।

पश्चिम रेलवे द्वारा एफओबी गर्डर लॉन्चिंग हेतु,मरीन लाइन्स स्टेशन पर मेजर ब्लॉक लिया जाएगा

पश्चिम रेलवे द्वारा मरीन लाइन्स स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 एवं 4 के बीच फुट ओवर ब्रिज के गर्डरों की रोड क्रेन के माध्यम से लॉन्चिंग हेतु 30/31 मई, 2026 की मध्यरात्रि में मेजर ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मरीन लाइन्स स्टेशन पर सभी लाइनों पर मेजर ब्लॉक लिया जाएगा।

इस ब्लॉक के कारण कुछ उपनगरीय सेवाएं रद्द अथवा आंशिक रूप से रद्द रहेंगी।

प्रभावित उपनगरीय सेवाओं का विवरण निम्नानुसार है:

शॉर्ट टर्मिनेट / शॉर्ट ओरिजिनेट होने वाली ट्रेनें:

- ट्रेन संख्या BO91014, जो बोरीवली से 00:10 बजे प्रस्थान कर चर्चगेट 01:15 बजे पहुंचती है, केवल मुंबई सेंट्रल स्टेशन तक ही चलेगी। अतः यह सेवा मुंबई सेंट्रल और चर्चगेट स्टेशनों के बीच रद्द रहेगी।
- ट्रेन संख्या VR91018, जो विरार से 23:49 बजे प्रस्थान कर चर्चगेट 01:26 बजे पहुंचती है, केवल मुंबई सेंट्रल स्टेशन तक ही चलेगी। अतः यह सेवा मुंबई सेंट्रल और चर्चगेट स्टेशनों के बीच रद्द रहेगी।
- ट्रेन संख्या BO91020, जो बोरीवली से 00:30 बजे प्रस्थान कर चर्चगेट 01:35 बजे पहुंचती है, केवल मुंबई सेंट्रल स्टेशन तक ही चलेगी। अतः यह सेवा मुंबई सेंट्रल और चर्चगेट स्टेशनों के बीच रद्द रहेगी।
- ट्रेन संख्या VR91024, जो विरार से 00:05 बजे प्रस्थान कर चर्चगेट 01:45 बजे पहुंचती है, केवल मुंबई सेंट्रल स्टेशन तक ही चलेगी। अतः यह सेवा मुंबई सेंट्रल और चर्चगेट स्टेशनों के बीच रद्द रहेगी।
- ट्रेन संख्या VR90011 चर्चगेट के बजाय मुंबई सेंट्रल से 04:25 बजे शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। अतः यह सेवा चर्चगेट और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच रद्द रहेगी।
- ट्रेन संख्या BO90015 चर्चगेट के बजाय मुंबई सेंट्रल से 04:28 बजे शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। अतः यह सेवा चर्चगेट और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच रद्द रहेगी।

चर्चगेट तक / से पहली एवं अंतिम सेवाएं निम्नानुसार रहेंगी:

- विरार से चर्चगेट के लिए अंतिम ट्रेन, ट्रेन संख्या VR91012, विरार से 23:30 बजे प्रस्थान करेगी तथा चर्चगेट 01:10 बजे पहुंचेगी।
- चर्चगेट से पहली निर्धारित स्लो ट्रेन, ट्रेन संख्या BO90025, चर्चगेट से 04:46 बजे प्रस्थान करेगी।
- चर्चगेट से पहली निर्धारित फास्ट ट्रेन, ट्रेन संख्या VR90021, चर्चगेट से 04:40 बजे प्रस्थान करेगी।
- यह भी सूचित किया जाता है कि रविवार, 31 मई, 2026 को दिन के समय कोई ब्लॉक नहीं रहेगा।

पश्चिम रेलवे विभिन्न गंतव्यों के बीच चलाएगी दो स्पेशल ट्रेनें

यात्रियों की सुविधा तथा बढ़ती यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे विभिन्न गंतव्यों के बीच विशेष किराये पर दो विशेष ट्रेनें चलाएगी, जिससे अतिरिक्त यात्री यातायात को सुगमता से नियंत्रित किया जा सके।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 09021/09022 मुंबई सेंट्रल – अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट स्पेशल

ट्रेन संख्या 09021 मुंबई सेंट्रल – अहमदाबाद स्पेशल रविवार, 31 मई 2026 को मुंबई सेंट्रल से 06:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 12:40 बजे अहमदाबाद पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09022 अहमदाबाद – मुंबई सेंट्रल स्पेशल रविवार, 31 मई 2026 को अहमदाबाद से 15:10 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 21:45 बजे मुंबई सेंट्रल पहुँचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच और वडोदरा स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में विस्टाडोम, एग्जीक्यूटिव चेयर कार, एग्जीक्यूटिव अनुभूति तथा एसी चेयर कार कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 09043/09044 बांद्रा टर्मिनस – अहमदाबाद / वटवा – बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल

ट्रेन संख्या 09043 बांद्रा टर्मिनस – वटवा स्पेशल सोमवार, 01 जून 2026 को बांद्रा टर्मिनस से 23:45 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 08:00 बजे वटवा पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09044 अहमदाबाद – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल सोमवार, 01 जून 2026 को अहमदाबाद से 03:50 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 12:15 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी और वडोदरा स्टेशनों पर ठहरेगी।

ट्रेन संख्या 09043 में उधना, आणंद और नडियाद स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव रहेगा। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09044 में भरूच और सूरत स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव रहेगा।

इस ट्रेन में एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास तथा सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच होंगे।

इन ट्रेन संख्याओं 09021, 09022, 09043 एवं 09044 की बुकिंग 30.05.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव एवं संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं।

गर्मी बन रही जानलेवा, एक दिन में 3400 मौतों का दावा ने बढ़ाई चिंता

नई दिल्ली। देश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी अब केवल असुविधा का विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का रूप लेती जा रही है। हाल ही में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट ने चौंकाने वाला दावा किया है कि अत्यधिक गर्मी के कारण देशभर में एक ही दिन में औसतन 3400 लोगों की मौत हो सकती है। वहीं यदि लू का प्रकोप लगातार पांच दिनों तक बना रहे तो इससे लगभग 30 हजार लोगों की जान जाने का खतरा पैदा हो जाता है। यह अध्ययन भारत में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव और उससे उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों की गंभीर तस्वीर प्रस्तुत करता है।

यह शोध इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर के शोधकर्ता पीयूष नारंग और अशोक गाडगिल के साथ अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के जलवायु विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। अध्ययन के लिए भारत के दस प्रमुख शहरों और विभिन्न राज्यों के तापमान, जनसंख्या घनत्व, मृत्यु दर तथा हीटवेव के प्रभावों से जुड़े आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। शोध के निष्कर्ष अंतरराष्ट्रीय जर्नल फ्रंटियर्स इन एनवायरनमेंटल हेल्थ में प्रकाशित हुए हैं, जिसने नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में तापमान लगातार खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अनेक क्षेत्रों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ते तापमान के कारण मानव शरीर की तापमान नियंत्रित करने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, हृदय संबंधी समस्याएं और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। शोध में यह भी सामने आया है कि पांच दिन तक चलने वाली तीव्र लू का सबसे अधिक असर उत्तर प्रदेश पर पड़ सकता है। अनुमान के मुताबिक केवल उत्तर प्रदेश में ही पांच दिन की हीटवेव के दौरान लगभग 8100 लोगों की मौत हो सकती है। इसके अलावा अहमदाबाद, जयपुर और सूरत जैसे शहरों में भी गर्मी के कारण प्रतिदिन लगभग 250 लोगों की जान जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट संरचनाओं की अधिकता, हरित क्षेत्र की कमी और बढ़ते प्रदूषण के कारण हीट आइलैंड प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, जिससे गर्मी का असर और अधिक घातक हो जाता है। रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है कि गर्मी से होने वाली कुल मौतों में लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों की है। जबकि देश की कुल जीडीपी में इन राज्यों का योगदान केवल 29 प्रतिशत के आसपास है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर और संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों में गर्मी का प्रभाव अधिक विनाशकारी साबित हो रहा है।

सप्ताह के दौरान सोना वायदा में 2681 रुपये, चांदी वायदा में 5346 रुपये और क्रूड ऑयल वायदा में 805 रुपये की भारी गिरावट

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 22 से 28 मई के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 7216572.63 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 263913.39 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 6952658.79 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल साप्ताहिक प्रीमियम टर्नओवर 35232.93 करोड़ रुपये का हुआ।

आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 160743.17 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सप्ताह के आरंभ में 159498 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 159500 रुपये और नीचे में 153451 रुपये पर पहुंचकर, 159606 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 2681 रुपये या 1.68 फीसदी की गिरावट के साथ 156925 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। गोल्ड-गिनी जून वायदा सप्ताह के अंत में 1739 रुपये या 1.35 फीसदी गिरकर 127275 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल जून वायदा 231 रुपये या 1.43 फीसदी लुढ़ककर सप्ताह के अंत में 15928 रुपये प्रति 1 ग्राम बंद हुआ। सोना-मिनी जून वायदा सप्ताह के आरंभ में 158390 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 159259 रुपये और नीचे में 153149 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 2669 रुपये या 1.68 फीसदी औंधकर 156336 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। गोल्ड-टेन जून वायदा सप्ताह के आरंभ में प्रति 10 ग्राम 160451 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 161298 रुपये और नीचे में 155525 रुपये पर पहुंचकर, 160872 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 2309 रुपये या 1.44 फीसदी गिरकर 158563 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा।

▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 263913 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 6952658 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ साप्ताहिक टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 160743 करोड़ रुपये का हुआ साप्ताहिक कारोबार

चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई वायदा सप्ताह के आरंभ में 273800 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 277399 रुपये के उच्च और 261000 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 274883 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 5346 रुपये या 1.94 फीसदी की गिरावट के साथ 269537 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा 4785 रुपये या 1.72 फीसदी घटकर सप्ताह के अंत में 273803 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो जून वायदा सप्ताह के अंत में 4754 रुपये या 1.71 फीसदी गिरकर 273840 रुपये प्रति किलो हुआ।

मेटल वर्ग में 29883.40 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जून वायदा सप्ताह के अंत में 2.25 रुपये या 0.17 फीसदी औंधकर 1360.4 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। जबकि जस्ता जून वायदा 2.55 रुपये या 0.7 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट सप्ताह के अंत में 367.55 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम जून वायदा 3.85 रुपये या 1 फीसदी बढ़कर 387.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर सप्ताह के अंत में बंद हुआ। जबकि सीसा जून वायदा सप्ताह के अंत में 1.8 रुपये या 0.88 फीसदी की बढ़त के साथ 207.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 73268.64 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जून वायदा सप्ताह के आरंभ में 9415 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 9555 रुपये के उच्च और 8409 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 805 रुपये या 8.62 फीसदी लुढ़ककर 8537 रुपये प्रति बैरल बंद हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जून वायदा 800 रुपये या 8.57 फीसदी गिरकर सप्ताह के अंत में 8539 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस जून वायदा सप्ताह के आरंभ में 303 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 315.8 रुपये के उच्च और 286.2 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 304.1 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 9.8 रुपये या 3.22 फीसदी की मजबूती के साथ 313.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बंद हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जून वायदा सप्ताह के अंत में 9.8 रुपये या 3.22 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 313.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर बंद हुआ।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जून वायदा सप्ताह के आरंभ में 990.4 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के अंत में 17.9 रुपये या 1.8 फीसदी गिरकर 975 रुपये प्रति किलो हुआ। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 91136.95 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 69606.21 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 22659.88 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 3525.70 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 135.87 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 3519.68 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 46898.59 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 26196.76 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 16.49 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सप्ताह के अंत में सोना के वायदाओं में 3064 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 26865 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 12721 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 184608 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 28190 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 10046 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 21926 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 56908 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 12658 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 20031 लोट के स्तर पर था।

श्रद्धालुओं की भीड़ से राजकोट स्टेशन बेहाल खिड़कियों से बच्चों को चढ़ाने तक पहुंची नौबत

राजकोट। गुजरात के राजकोट रेलवे स्टेशन पर इन दिनों यात्रियों की भारी भीड़ और अव्यवस्था ने रेलवे प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुरुषोत्तम मास के अवसर पर द्वारका जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में अचानक हुई वृद्धि के कारण स्टेशन पर हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं। भीड़ इतनी अधिक हो गई कि कई यात्रियों को अपने छोटे बच्चों को ट्रेन के दरवाजों के बजाय खिड़कियों से अंदर पहुंचाने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्टेशन पर सामने आए इन दृश्यों ने न केवल यात्रियों की परेशानी को उजागर किया है, बल्कि रेलवे की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन व्यवस्था की पोल भी खोल दी है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही सीट हासिल करने की होड़ मच गई। यात्रियों के बीच धक्का-मुक्की, अफरा-तफरी और चीख-पुकार का माहौल बन गया। कई परिवारों ने इस आशंका से कि उन्हें ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी, अपने बच्चों को पहले खिड़कियों से अंदर बैठाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों ने भी रेलवे प्रशासन के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्रियों का कहना है कि यदि समय रहते पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि रेलवे प्रशासन ने मामले को लेकर अपनी सफाई भी पेश की है। अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में थी और संबंधित ट्रेन में पर्याप्त जगह उपलब्ध थी। रेलवे के अनुसार यात्रियों ने जल्दबाजी और सीट सुरक्षित करने की मानसिकता के कारण स्वयं ऐसी स्थिति पैदा कर दी। अधिकारियों ने माना कि खिड़कियों से बच्चों को ट्रेन में चढ़ाना बेहद जोखिम भरा कदम है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी।

दरअसल, पुरुषोत्तम मास के दौरान द्वारका, सोमनाथ और अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में

हर वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजकोट स्टेशन से यात्रा कर रहे हैं। लेकिन यात्रियों का आरोप है कि मांग के अनुरूप अतिरिक्त ट्रेनों और जनरल डिब्बों की व्यवस्था नहीं की गई। परिणामस्वरूप सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक भीड़ ट्रेनों पर टूट पड़ी है।

रेलवे यात्रियों और सामाजिक संगठनों ने राजकोट डिवीजन के अधिकारियों से अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाने तथा मौजूदा ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त ट्रेनों या डिब्बों को मंजूरी देने का अधिकार रेलवे बोर्ड के पास है और स्थानीय स्तर पर सीमित संसाधनों के भीतर ही व्यवस्था की जा सकती है। इस जवाब से यात्रियों में नाराजगी और बढ़ गई है।

विशेष रूप से यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पश्चिम रेलवे के राजकोट मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 2711 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड आय अर्जित की है। इसके बावजूद यात्रियों का कहना है कि बुनियादी सुविधाओं, सुरक्षा प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं दे रहे हैं। यात्रियों का आरोप है कि रेलवे राजस्व बढ़ाने पर तो ध्यान दे रहा है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिल रही।

रेलवे विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान हालात को देखते हुए राजकोट स्टेशन पर वही स्थिति पैदा होने का खतरा है, जो कुछ महीने पहले सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली थी। अप्रैल महीने में उधना स्टेशन पर भी अत्यधिक भीड़ और अपर्याप्त ट्रेनों के कारण गंभीर अव्यवस्था फैल गई थी। उस घटना के बाद रेलवे ने कई सुधारात्मक कदम उठाने का दावा किया था, लेकिन राजकोट की स्थिति यह संकेत देती है कि उन अनुभवों से पर्याप्त सबक नहीं लिया गया।

आंकड़ों पर नजर डालें तो राजकोट रेलवे डिवीजन से हर वर्ष लगभग 1.30 करोड़ यात्री यात्रा करते हैं। इसका मतलब है कि प्रतिदिन औसतन 35 हजार से अधिक लोग रेलवे सेवाओं का उपयोग करते हैं। त्योहारों, धार्मिक आयोजनों और छुट्टियों के दौरान यह संख्या 50 हजार से भी अधिक पहुंच जाती है। ओखा-गोरखपुर, पोरबंदर-मुजफ्फरपुर और अन्य लंबी दूरी की ट्रेनों में क्षमता से कई गुना अधिक यात्रियों के सफर करने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन डिब्बों की क्षमता लगभग 100 यात्रियों की होती है, उनमें 300 से अधिक लोग यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में एक सीट पर तीन-तीन यात्रियों का दबाव बन रहा है और यात्रियों के बीच जगह को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अब शनिवार और रविवार की छुट्टियों के कारण यात्रियों की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में रेलवे प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती भीड़ को नियंत्रित करने, पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते अतिरिक्त कोच, विशेष ट्रेनें और प्रभावी भीड़ प्रबंधन व्यवस्था नहीं की गई तो किसी बड़ी दुर्घटना या अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल राजकोट रेलवे स्टेशन की स्थिति रेलवे प्रशासन के लिए एक बड़ी चेतावनी बनकर सामने आई है, जिस पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

31 मई से 15 जुलाई तक प्रत्येक रविवार और बुधवार को गांधीग्राम – प्रयागराज जंक्शन के बीच चलेगी द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा भावनगर मंडल से एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त रेल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। गांधीग्राम और प्रयागराज जंक्शन के बीच विशेष किराये पर द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, भावनगर मंडल श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार, इस विशेष ट्रेन का संचालन निम्नानुसार किया जाएगा—

ट्रेन संख्या 04112 गांधीग्राम – प्रयागराज जंक्शन द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 31 मई, 2026 से 15 जुलाई, 2026 तक प्रत्येक रविवार और बुधवार को गांधीग्राम से शाम 17:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन रात्रि 20:00 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 04111 प्रयागराज जंक्शन–गांधीग्राम द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 30 मई, 2026 से 14 जुलाई, 2026 तक प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को प्रयागराज जंक्शन से शाम 16:15 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन दोपहर 15:30 बजे गांधीग्राम पहुंचेगी।

दोनों दिशाओं में यह ट्रेन निम्नलिखित स्टेशनों पर ठहरेगी— चांदखेड़ा रोड, मेहसाणा जंक्शन, पालनपुर जंक्शन, आबू रोड, सुमेरपुर जवाई बाँध, फालना, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर जंक्शन, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह, टूण्डला जंक्शन, इटावा जंक्शन, गोविंदपुरी, फतेहपुर।

इस विशेष ट्रेन में द्वितीय श्रेणी सामान्य (GS), शयनयान (Sleeper) एवं थर्ड एसी (3rd AC) श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे।

ट्रेन संख्या 04112 के लिए टिकटों की बुकिंग 30 मई, 2026 (शनिवार) से सभी यात्री आरक्षण केन्द्रों तथा IRCTC की वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन के समय, ठहराव एवं संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

पश्चिम रेलवे द्वारा अहमादाबाद और मुंबई के बीच दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष किराये पर मुंबई और अहमदाबाद के बीच दो जोड़ी विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।। इन विशेष ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

1. ट्रेन संख्या 09021/09022 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल एसी सुपरफास्ट स्पेशल

ट्रेन संख्या 09021 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट स्पेशल 31 मई, 2026 (रविवार) को मुंबई सेंट्रल से 06:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 12:40 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09022 अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल एसी सुपरफास्ट स्पेशल 31 मई, 2026 (रविवार) को अहमदाबाद से 15:10 बजे प्रस्थान करेगी तथा 21:45 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच एवं वडोदरा स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में (शताब्दी रेक) एग्जीक्यूटिव चेयरकार, एसी चेयरकार, अनुभूति क्लास कोच और एक विस्टाडोम कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 09044/09043 अहमदाबाद–बांद्रा टर्मिनस–वटवा सुपरफास्ट स्पेशल

ट्रेन संख्या 09044 अहमदाबाद–बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल 01 जून, 2026 (सोमवार) को अहमदाबाद से 03:50 बजे प्रस्थान करेगी तथा 12:15 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09043 बांद्रा टर्मिनस–वटवा सुपरफास्ट स्पेशल 01 जून, 2026 (सोमवार) को बांद्रा टर्मिनस से 23:45 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन (मंगलवार) को 08:00 बजे वटवा पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 09044 वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, पालघर एवं बोरीवली तथा ट्रेन संख्या 09043 बोरीवली, पालघर, वापी, उधना, वडोदरा, आनंद एवं नडियाद स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में एसी-3टियर और स्लीपर श्रेणी के कोच रहेंगे।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भावनगर की छमाही बैठक संपन्न

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), भावनगर की छमाही बैठक का आयोजन दिनांक 29 मई, 2026 (शुक्रवार) को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, भावनगर में अध्यक्ष – नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर श्री दिनेश वर्मा की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक किया गया।

बैठक में भावनगर स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, बैंकों एवं उपक्रमों के कार्यालय प्रमुखों, राजभाषा अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। बैठक के दौरान सदस्य कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग एवं प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा राजभाषा संबंधी महत्वपूर्ण मदों पर प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

इस अवसर पर राजभाषा हिंदी पत्रिका प्रकाशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय को "सर्वश्रेष्ठ शील्ड", सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को "उत्कृष्ट शील्ड" तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को "प्रशंसनीय शील्ड" प्रदान कर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष महोदय ने सभी विजेता संस्थाओं को बधाई देते हुए कहा कि अन्य कार्यालय भी इनसे प्रेरणा लेकर राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में सक्रिय योगदान देंगे।

श्री दिनेश वर्मा ने गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त करने पर बल देते हुए सभी कार्यालयों से राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का आग्रह किया। अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा ने अपने संबोधन में कर्मचारियों को विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक के अंत में सचिव- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति श्री रामप्रीत मौर्य ने अध्यक्ष महोदय सहित सभी सदस्य कार्यालयों एवं प्रतिनिधियों का सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता हेतु आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ अनुवादक श्री परेश बी. मजीठिया द्वारा किया गया।

बैठक में प्रमुख रूप से मंडल लेखा परीक्षा कार्यालय, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, केंद्रीय विद्यालय, आयकर कार्यालय, भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL), मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सहित विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों एवं उपक्रमों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

गांधीग्राम और प्रयागराज के बीच द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन

यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा गांधीग्राम और प्रयागराज के बीच विशेष किराये पर द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इस विशेष ट्रेन का संचालन निम्नानुसार किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 04112/04111 गांधीग्राम–प्रयागराज द्वि-साप्ताहिक स्पेशल (28 फेरे)

ट्रेन संख्या 04112 गांधीग्राम – प्रयागराज द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 31 मई, 2026 से 15 जुलाई, 2026 तक प्रत्येक रविवार और बुधवार को गांधीग्राम से 17:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 20:00 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 04111 प्रयागराज–गांधीग्राम द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 30 मई, 2026 से 14 जुलाई, 2026 तक प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को प्रयागराज से 16:15 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 15:30 बजे गांधीग्राम पहुंचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन चांदखेड़ा रोड, महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, सुमेरपुर जवाई बाँध, फालना, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह, टूण्डला, इटावा, गोविंदपुरी एवं फतेहपुर स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में द्वितीय सामान्य श्रेणी, स्लीपर एवं एसी-3 टियर श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 04112 की बुकिंग 30 मई, 2026 से सभी यात्री आरक्षण केन्द्रों तथा IRCTC की वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन के समय, ठहराव एवं संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

अहमदाबाद मंडल के सी एंड डब्ल्यू (C&W) कर्मचारियों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई : टला एक्सप्रेस ट्रेन का कोच डिटैचमेंट

मात्र 28 मिनट में क्षतिग्रस्त वाल्व को बदलकर ट्रेन को गंतव्य के लिए किया रवाना,DRM श्री वेद प्रकाश ने रेल कर्मियों को 5,000 के सामूहिक पुरस्कार से नवाजा

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के कैरिज एवं वैगन (सी एंड डब्ल्यू) विभाग के कर्मचारियों ने आज अपनी तकनीकी दक्षता, दूरदर्शी योजना और उत्कृष्ट समन्वय का परिचय देते हुए एक बड़ा संकट टाल दिया। रेल कर्मियों की मुस्तैदी से ट्रेन संख्या 22950 देहरादून–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस के एक कोच को अलग (डिटैच) होने से बचा लिया गया और ट्रेन का सुचारु व सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित किया गया।

क्या थी तकनीकी समस्या?

दिनांक 29 मई 2026 को उत्तर पश्चिम रेलवे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यात्रा के दौरान ट्रेन संख्या 22950 दिल्ली सराय रोहिल्ला-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस के कोच संख्या M-2 में FIBA (Failure Indication and Brake Application) की स्थिति उत्पन्न हो गई। आबू रोड स्टेशन पर गहन जांच के दौरान तकनीकी टीम ने पाया कि डुप्लेक्स चेक वाल्व क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे लगातार एयर लीकेज हो रही थी। इस लीकेज के कारण अग्रणी ट्रॉली के दोनों एयर स्प्रिंग्स डिफ्लेट (पिचक) गए थे। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए, ट्रेन को सी एंड डब्ल्यू स्टाफ की निगरानी (एस्कॉर्टिंग) में 60 किमी प्रति घंटे की प्रतिबंधित गति से आगे चलाने की अनुमति दी गई।

अहमदाबाद मंडल की तैयारी

प्रातः 06:30 बजे अहमदाबाद कंट्रोल कार्यालय को यह सूचना मिली कि अहमदाबाद स्टेशन पहुंचने पर प्रभावित कोच को ट्रेन से अलग करना पड़ सकता है। कोच डिटैच होने से यात्रियों को भारी असुविधा होती और ट्रेन भी अत्यधिक विलंबित होती।

सूचना मिलते ही अहमदाबाद मंडल के सी एंड डब्ल्यू पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। टीम ने बिना समय गंवाए आवश्यक उपकरणों, फिटिंग्स और अतिरिक्त डुप्लेक्स चेक वाल्व की व्यवस्था की और ट्रेन के आने से पहले ही प्लेटफॉर्म संख्या 7 पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हो गए।

मात्र 28 मिनट में 'मिशन सफल'

ट्रेन अपने निर्धारित समय से 62 मिनट की देरी से प्रातः 08:27 बजे अहमदाबाद स्टेशन पहुंची। ट्रेन के रुकते ही सी एंड डब्ल्यू की कुशल टीम ने युद्धस्तर पर काम शुरू किया। कर्मचारियों ने अपने तकनीकी कौशल का परिचय देते हुए मात्र 28 मिनट के रिकॉर्ड समय में क्षतिग्रस्त डुप्लेक्स चेक वाल्व को बदल दिया। इसके परिणामस्वरूप कोच को तुरंत फिर से सेवा योग्य (फिट) बना दिया गया। ट्रेन को बिना किसी अतिरिक्त समयहानि के और बिना कोच डिटैच किए सामान्य गति से आगे के गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया।

मंडल रेल प्रबंधक द्वारा सामूहिक पुरस्कार की घोषणा

अहमदाबाद मंडल के रेल कर्मियों की इस समर्पित कार्यशैली और त्वरित निर्णय क्षमता के कारण न केवल एक संभावित कोच डिटैचमेंट टला, बल्कि ट्रेन की समयबद्धता (Punctuality) पर पड़ने वाले असर को भी न्यूनतम रखा जा सका। मंडल रेल प्रबंधक (DRM) अहमदाबाद, श्री वेद प्रकाश ने कर्मचारियों की इस सराहनीय कार्यकुशलता, सतर्कता और तत्परता की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने इस उत्कृष्ट कार्य के लिए संबंधित सी एंड डब्ल्यू टीम को 5,000 का सामूहिक पुरस्कार देने की घोषणा की है।

साधु–साध्वियों की सुरक्षा को लेकर जैन समाज का मौन आक्रोश, सूरत में निकली 5 हजार लोगों की विशाल रैली

सूरत। मध्यप्रदेश के रीवा में दिगंबर जैन समाज की दो साध्वियों—आचार्य विद्यासागर जी महाराज की शिष्याएं श्रुतमती माताजी और उपशम माताजी—की कथित सुनियोजित सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु तथा गुजरात के राजकोट जिले के चोटिला क्षेत्र में पन्यास श्री ओंकारशेखर विजय जी महाराज के सड़क हादसे में देवलोकगमन की घटनाओं ने पूरे देश के जैन समाज को गहरे शोक और आक्रोश से भर दिया है। इन घटनाओं को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन, श्रद्धांजलि सभाएं और न्याय की मांग को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को सूरत में सकल जैन समाज के तत्वावधान में एक विशाल मौन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लेकर साधु-साध्वियों की सुरक्षा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठाई।

सुबह से ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों से समाजजन पार्ले पॉइंट स्थित सरगम शॉपिंग सेंटर परिसर में एकत्र होने लगे थे। निर्धारित समय पर शुरू हुई यह मौन रैली अनुशासन, एकता और सामाजिक चेतना का अनूठा उदाहरण बन गई। रैली में दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी और तेरापंथी सहित जैन समाज के सभी प्रमुख पंथों के लोग एक मंच पर दिखाई दिए। समाज के वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। आयोजन की विशेषता यह रही कि पूरे कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की नारेबाजी नहीं की गई और सभी प्रतिभागियों ने मौन रहकर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।

रैली में शामिल पुरुष सफेद पैंट-शर्ट और महिलाएं नारंगी साड़ी पहनकर पहुंचीं। हजारों लोगों की यह अनुशासित भीड़ जब शहर की सड़कों से गुजर रही थी, तब पूरे वातावरण में गंभीरता और संवेदना का भाव दिखाई दे रहा था। लोगों के हाथों में न्याय और सुरक्षा की मांग से जुड़े संदेश लिखे बैनर और तख्तियां थीं। शहरवासियों ने भी इस रैली को गंभीरता से देखा और बड़ी संख्या में लोगों ने समाज की मांगों का समर्थन किया।

जैन समाज के नेताओं ने कहा कि रीवा में हुई घटना केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि ऐसी घटना है जिसकी निष्पक्ष और गहन जांच आवश्यक है। उनका कहना था कि यदि किसी प्रकार की साजिश, लापरवाही या

आपराधिक कृत्य सामने आता है तो दोषियों को कठोरतम दंड मिलना चाहिए। समाज का मानना है कि साध्वियां और साधु समाज के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं, जो त्याग, तपस्या और अहिंसा का जीवन जीते हैं। ऐसे संतों की असामयिक मृत्यु केवल एक समुदाय की नहीं बल्कि पूरे समाज की क्षति है।

रैली शांतिपूर्वक कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां समाज के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि रीवा प्रकरण के मुख्य आरोपियों और अपराध में सहयोग करने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और उन्हें कठोरतम सजा दी जाए। समाज ने कहा कि न्याय में देरी से लोगों का विश्वास कमजोर होता है, इसलिए इस मामले में त्वरित कार्रवाई बेहद आवश्यक है।

ज्ञापन में केवल दोषियों को सजा देने की मांग ही नहीं की गई, बल्कि देशभर में पदविहार करने वाले साधु-संतों और साध्वियों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने की भी मांग उठाई गई। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि जैन संत और साध्वियां वाहन का उपयोग नहीं करते तथा पैदल यात्रा करते हुए गांव-गांव और शहर-शहर धर्म, संस्कृति, नैतिकता और अहिंसा का संदेश पहुंचाते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। उन्होंने सुझाव दिया कि साधु-संतों के पदविहार मार्गों की पूर्व जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी जाए और आवश्यकतानुसार सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान समय में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यस्त राजमार्गों और तेज रफ्तार वाहनों के बीच पैदल यात्रा करने वाले साधु-संतों की सुरक्षा एक गंभीर विषय बन चुका है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। इसलिए केवल संवेदना व्यक्त करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि स्थायी समाधान भी तलाशना होगा।

रैली के दौरान कई वक्ताओं ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज की तपस्या, शिक्षा और समाज निर्माण में उनके योगदान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनकी शिष्याओं की मृत्यु से जैन समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। वहीं पन्यास श्री ओंकारशेखर विजय जी महाराज के देवलोकगमन को भी समाज ने अत्यंत दुखद बताया। वक्ताओं ने कहा कि संत समाज का जीवन मानवता की सेवा और आत्मिक उत्थान के लिए समर्पित होता है, इसलिए उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

रैली में पांच हजार से अधिक लोगों की भागीदारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि जैन समाज इस मुद्दे को लेकर अत्यंत गंभीर है। समाज के विभिन्न संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई और साधु-साध्वियों की सुरक्षा को लेकर ठोस पहल नहीं की गई, तो देशभर में व्यापक स्तर पर आंदोलन किए जाएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके सभी आंदोलन अहिंसक, लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में ही होंगे।

सूरत में आयोजित यह विशाल मौन रैली केवल विरोध प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह जैन समाज की एकजुटता, अनुशासन, सामाजिक जिम्मेदारी और न्याय के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक बनकर सामने आई। हजारों लोगों की मौन उपस्थिति ने यह संदेश दिया कि समाज अपने संतों और साध्वियों की सुरक्षा को लेकर अब किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जैन समाज को उम्मीद है कि केंद्र और राज्य सरकारें इस गंभीर विषय पर संवेदनशीलता दिखाते हुए आवश्यक कदम उठाएंगी, ताकि भविष्य में कोई साधु या साध्वी असुरक्षा का शिकार न हो और देश की आध्यात्मिक परंपरा सुरक्षित रह सके।